

काम करते हैं, जैसे ओडिशा में काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में काम करते हैं, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में वन कामगारों की भी कोऑपरेटिव सोसायटीज़ हैं और उनको भी वन उपज के माध्यम से चाहे महुआ फ्लावर हो, तेंदुपत्ता हो और बाकी बहुत सारे उत्पादन को कोऑपरेटिव क्षेत्र के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। आज बैंकिंग में एक बात निश्चित है। कुछ अपवाद, इधर-उधर की घटनाएं, दुर्घटनाएं, बैंकिंग क्षेत्र में, कोऑपरेटिव में हुई होंगी, लेकिन आज अगर आप मोटा-मोटी देखें, तो जो बैंकिंग की reach है, चाहे nationalized banks हों या प्राइवेट बैंक्स हो, उनका जाल पूरे देश में नजर आता है। आज भी ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा, जहां पर बैंकिंग की जरूरत हो और बैंक न पहुंची हो और अगर वहां बैंक पहुंची है, तो केवल कोऑपरेटिव बैंक पहुंची होगी। यह बहुत जरूरी है और इसी वजह से आज यह जो बिल है, इसमें खाली यूनिवर्सिटी तो एक माध्यम है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, वहां से अच्छे मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स तैयार हों, वहां पर जाकर फैकल्टी उनको नई-नई techniques सिखाए। सर केवल नाम के लिए कोऑपरेटिव है, लेकिन साथ-साथ आज आधुनिक युग में उनके लिए sky is the limit. उस वजह से उनको अगर नई techniques, नई चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, तो उसका हम लोगों को सहर्ष स्वागत करना चाहिए। यह जो बिल है, वह कोऑपरेटिव क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए, हमारे देश में नई पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए, क्योंकि नई पीढ़ी मैनेजमेंट में बाकी चीजों में चली जाती है। कोई फाइनेंस में चला जाएगा, कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाता है, लेकिन रूरल मैनेजमेंट के क्षेत्र में नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, जिसके माध्यम से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपने भविष्य को बना सकते हैं।

यह भी इस बिल का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं इस वजह से इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हुए पुनश्च: सरकार को भी बधाई दूंगा कि त्रिभुवन दास पटेल, जिन्हें गुजरात में 'त्रिभुवन काका' भी कहते हैं, हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। हमारे नरहरी भाई और मेरे, हम दोनों के पूर्वज एक ही जिले के हैं, इसलिए नरहरी भाई को भी मालूम है कि पूरा गुजरात 'त्रिभुवन काका' के नाम से त्रिभुवन दास पटेल के योगदान को बहुत महत्व देता है, अतः मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देते हुए इसका पुरजोर समर्थन करता हूं।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform that the Business Advisory Committee in its meeting held on the 1st of April, 2025 has allotted time for Government legislative business as follows:

1. Consideration and passing of the Immigration and Foreigners **Five hours.**

Bill, 2025, as passed by Lok Sabha.

2. Consideration and passing of the following Bills after they are considered and passed by Lok Sabha:-

- | | |
|--|---|
| (i) The Waqf (Amendment) Bill, 2025, as reported by the Joint Committee. | Eight hours to be discussed together |
| (ii) The Mussalman Waqf (Repeal) Bill, 2024. | |
| (iii) The Indian Ports Bill, 2025. | Two hours. |

The Committee also recommended that the House may dispense with the lunch hour on 2nd and 3rd April, 2025, and also sit late to complete the listed business on both days. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I am sorry. The Government said that the Indian Ports Bill will not be taken up during this Session. That is what they said. So it is not three hours in this Session. I just want to clarify it.

MR. CHAIRMAN: Your point is noted. Shri P.P. Suneer.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI) *in the Chair.*]

The “Tribhuvan” Sahkari University Bill, 2025- *Contd.*

SHRI P.P. SUNEER (Kerala): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Sir, I rise to speak on the “Tribhuvan” Sahkari University Bill with a sense of concern. While the University is meant to serve the cooperative sector, its governance structure tells a different story. In true BJP fashion, decision-making is excessively centralised. The proposed governing board is packed with bureaucrats, and not a single expert from the field of education has been included. What does this reveal? A Government that is short-sighted, that does not recognize the importance of educational expertise in running a university, let alone one dedicated to the cooperative movement!

The story of the man after whom this University is named, Tribhuvandas Kishbhai Patel, is a story of grassroots empowerment. The foundations of Amul were laid by him, and it was the technological innovations and social entrepreneurship of Dr. Verghese Kurien and Shri H.M. Dalaya that transformed it into a globally recognized branch. The cooperative movement was strengthened with technology and innovation by Dr. Verghese Kurien and paved the way for India's self-sufficiency